Shri Sham Nath: I require notice, Sir.

Shri M. K. Kumaran: The hon. Deputy Minister gave a list of languages used in international broadcasts. May I know whether Government propose to use Spanish and Russian, which are very important international languages for external broadcasts?

Shri Sham Nath: It is a suggestion for action, Sir.

Shri U. M. Trivedi: Will the hon. Minister be pleased to state if the broadcast in Chinese is done by Chinamen or by Indians employed to carry out these broadcasts?

Shri Sham Nath: I shall collect this information if the hon. Member gives notice.

Shri P. R. Chakraverti: Is it not a fact that the South American countries are now taking a new stride towards freedom and are keen on acquainting themselves with the experiments that are going on in democratic countries of which the leading country is India, and if so, may I know why the Government is reluctant to give them correct information, thereby serve the cause of freedom and at the same time weaning them away from the countries which are trying to ridicule India in the world's eye.....

Mr. Speaker: That is not a question; it is a regular speech.

Shri P. R. Chakraverti: The Minister has said.....

Mr. Speaker: Order, order. No argument can be given, because he has made a speech and not put a question.

Shri P. R. Chakraverti: I will put the question. In view of the fact that some interested countries are trying to ridicule India in the world's eye, do the Government think it now advisable to take prompt measures for giving correct information to the South American countries?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): The question, Sir, if I may say so, is like the question: "Has the Government given up beating its grandmother every morning". It starts with the presumption that Government has decided or it thinks that it is not necessary to give information to South-American countries which is absurd, if I may say so. We attach the greatest importance to Latin American countries, and if our approach to it has been somewhat limited it is due to our technical difficulties and other matters. Recently we have had Ambassadors in most of them. Even now we do not cover all of them. These are the difficulties and not any lack of will on our part. The whole question is that a change of policy is needed. We lacked the will to approach them, and now we should approach them.

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा हिन्दी में प्रमाणपत्रों का दिया जाना

*१६२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा प्रचार सम्मेलन ने अपनी हाल ही की वर्धा में हुई बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा उनके मंत्रालय से तथा फिल्म सेंसर बोर्ड से अनुरोध किया है कि हिन्दी फिल्मों को केवल हिन्दी में ही प्रमाणपत्र दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस अपील पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गोपाल रेड्डी को क्या कोई इस प्रकार का शिष्टमंडल मिला था और उन्होंने उसको इस प्रकार का

आश्वासन दिया था कि जो हिन्दी के चलचित्र हैं, उनको जो प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, वे हिन्दी में ही दिये जायेंगे ?

Shri Sham Nath: We had this question examined by the Law Ministry, and the Law Ministry advised us that since the forms have been fixed statutorily by rules framed under the Act it would not be possible to issue certificates in Hindi without amending the rules.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न यह था कि सूचना एवं प्रसारण] मंत्री श्री गोपाल रेड्डी साहब को कोई इस प्रकार का शिष्टमंडल मिला था जिस ने उनसे अनुरोध किया था कि हिन्दी के चलचित्रों को जो प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, वे हिन्दी में ही दिये जायें और मंत्री महोदय ने क्या इसके बारे में कोई अनुकूल आश्वासन दिया था ?

श्री शाम नाथ : मैंने अभी अर्ज किया है कि जिस रेजोल्यूशन का हवाला दिया गया है उसको हमने बहुत तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह रेजोल्यूशन हमें नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : रेजोल्यूशन के बारे में वह नहीं पूछ रहे हैं। जहां तक मैं समझा हूं वह पूछते हैं कि क्या कोई डेलीगेशन आया था और श्री गोपाल रेड्डी साहब से मिला था और मिनिस्टर साहब ने उनको इसके बारे में कुछ भरोसा दिलाया था ?

श्री शाम नाथ : मुझे इसका कोई इल्म नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय फिल्मों को प्रमाणपत्र देने की क्या व्यवस्था है और वे किन किन भाषाओं में दिये जाते हैं ?

श्री शाम नाथ : सर्टिफिकेट्स का जहां तक ताल्लुक है, वे इंग्लिश में इशू होते है।

श्री रघुनाथ सिंह : जिस रूल का हवाला दिया है उसमें संशोधन करने की कोई योजना क्या आप बना रहे हैं ताकि हिन्दी जोकि राष्ट्र भाषा है, उसमें भी उनको दिया जा सके ?

श्री शाम नाथ : इस सवाल पर गौर हुआ था लेकिन क्योंकि कुछ टैक्नीकल डिफिकलटी थी इसलिये इस सवाल को छोड़ दिया गया। लेकिन हो सकता है कि इस पर दुबारा गौर किया जाए।

श्री रघुनाथ सिंह : पहले मिनिस्टर साहब ने रूल का हवाला दिया और अब कहते हैं कि टैक्नीकल डिफिकलटी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या टैक्नीकल डिफिकलटी है या रूल की कोई डिफिकलटी है ?

श्री शाम नाथ : मैंने अर्ज किया है कि इस मामले पर हमने ला मिनिस्ट्री से एडवाइस ली थी और ला मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जब तक रूल को एमेंड न किया जाए, उस वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि रूल को एमेंड करने का क्या कोई इरादा है ?

श्री शामनाथ : मैंने अर्ज किया कि इस पर गौर किया जाएगा।

श्री ज० ब० सिंह : मैं भी यही सवाल पूछ रहा था कि ....

अध्यक्ष महोदय : अगर यही पूछ रहे थे तो अब पूछने की जरूरत नहीं रही।

श्री सिंहासन सिंह : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रूल को एमेंड किए बगैर यह नहीं हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि रूल को एमेंड करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है और क्या रूल को एमेंड करने की कोशिश हो रही है ?

श्री त्यागी : मिनिस्ट्री रूल को एमेंड कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल एक माननीय

सदस्य कर रहे हैं और जवाब भी दूसरे माननीय सदस्य दे रहे हैं, मैं क्या करूं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किसी रूल को बदलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं मिनिस्ट्री इस पर जरूर गौर करेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जिस तरह से हिन्दी के जो सिनेमा हैं, उनको प्रमाणपत्र देने के सम्बन्ध में यह शिष्टमंडल मिला था और उसने मांग की थी कि उनको हिन्दी में ही प्रमाणपत्र दिये जायें, इसी तरह से तामिल, तेलेगू, बंगला आदि जो क्षेत्रीय भाषायें हैं, उनमें जो सिनेमा तैयार होते हैं, उनको भी क्या प्रमाणपत्र उन्हीं भाषाओं में दिये जा सकें, क्या इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था की जाएगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह दिक्कत-तलब बात मालूम होती है कि सात आठ दस भाषाओं में अलग अलग प्रमाण-पत्र दिये जायें । यकायक तो मेरी समझ में यह काफी दिक्कत-तलब आती है ।

China's Note dated 31st May, 1962

\+

*1630. **Shri Hari Vishnu Kamath:**
Shri Shree Narayan Das:
Shri Hem Barua:
Shri Bhakt Darshan:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the reference to Nepal, Sikkim and Bhutan in the Chinese note dated the 31st May, 1962 replying to India's note regarding proposed Sino-Pak. border talks dated the 10th May, 1962; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir.

(b) In our protest note of 10th May 1962, we drew the attention of the Government of China to the fact that China had no common border with Pakistan whether in the West or in the East, and cited the two terminal points of our border to prove it. It was not meant to be a complete description but enough to show that China and Pakistan had no common border. The Government of China in their reply gave this description a meaning which our note did not seek to convey, and drew certain conclusions therefrom which are calculated to affect our relations with Nepal, Sikkim and Bhutan.

It is needless to reiterate that we have close and enduring relations with Nepal based on mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty.

In regard to Bhutan, we have special treaty obligations and, at the request of the Government of Bhutan, we have at various times taken up with the Government of China matters such as Chinese cartographic aggression on Bhutan, the violation of Bhutan's air space by Chinese aircraft and the protection of Bhutan's interests in Tibet.

As to Sikkim, our position is clear. The Government of India are entirely responsible for the defence and external relations of Sikkim and no foreign power has any right to interfere in Sikkim.

Shri Hari Vishnu Kamath: China in its note replying to India's note of the 10th May says that Nepal does not exist, Sikkim does not exist and Bhutan does not exist. Is it clear evidence of China's *mala fides* and has Government got any other information in its possession to show that these expressions are an outward sign of an inward design to liberate these territories in the Chinese meaning of the word "liberation" and, if so, what is Government's reaction to that?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of